Wednesday

Vijay Kumar Jha.
Asst Prof
Deptt in History
V.S.J College Rajnagar

Degree Part III

Paper - VIII

British Mandate in Iraq.

प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों ने प्रजातंत्र के सिद्धान्तों की रक्षा करने का वचन दिया था। मित्र राष्ट्रों ने राष्ट्रसंघ के संरक्षण में उपनिवेशों को विकासित और आत्म निर्भर हो जाने का संकल्प लिया था कि उपनिवेश को स्वतंत्र कर दिया जाय। इसी व्यवस्था को Mandate System कहा गया।

प्रथम विश्व युद्ध तक इराक ओटोमन साम्राज्य के अधीन रहा इसमें बसरा, बगदाद और मोसुल था तथा ये फारस की खाड़ी के तट पर होने के कारण ब्रिटेन के लिये विशेष महत्व रखता था। युद्ध आरम्भ होते ही ब्रिटेन ने इन प्रदेशों कि रक्षार्थ एक बड़ी सेना भेजी और इन प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया। युद्ध के बाद इन प्रदेशों को इराक के नाम से जानते है। इराक पर ब्रिटीश सेना का नियंत्रण बढ़ गया। ब्रिटेन को अरब राष्ट्रवाद से कोई संबंध नहीं थे वे तो इराक को लूटने खसोटने लगा। ओटोमन साम्राज्य के अधीन जो इराकियों को टैक्स देना पड़ता था वह अब तीन गुणा हो गया अर्थात भारतीय उपनिवेश से जो ब्रिटीश टैक्स वसूलता था उससे भी ज्यादा हुआ टैक्स कि ये रकम अँगरेजों के ऐसो आराम पर खर्च होता था इराक में जो ब्रिटीश-भारतीय फौज थी उसका भी कुल खर्च इराक का ही उठाना पड़ता था। अतः इराक के जनता में भारी असंतोष फैल गया था।

युद्ध काल में इराकियों को स्वशासन के अधिकार देने का वचन मित्र राष्ट्रों ने किया था और इराकियों ने इन्हीं प्रलोभनों

Scanned with Cam

पर मित्रराष्ट्रों की सहायता किया था किन्तु ब्रिटेन ने इराकियों को स्वतंत्र करने के बदले उसे गुलामी की जंजीर में जकड़ने का प्रयास किया। किन्तु इराक पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद लादना कठिन था अतः इराक को Mandate system के अन्तर्गत रख दिया गया और ब्रिटेन को राष्ट्र संघ द्वारा इराक का संरक्षक शासक बना दिया गया सरपर्सी कॉक्स इराक के हाई कमिश्नर नियुक्त किये गये। सभी मामलों के अंतिम निर्णय हाई कमिश्नर को मिला। किन्तु अरबवासी स्वतंत्र शासन चाहते थे अतः उन्होंने इस व्यवस्था को नहीं माना।

1921 ई० में औपनिवेशिक मंत्री चर्चिल ने अरब में एक सम्मेलन बुला-कर फैजल को इराक का राजा बना दिया जिसे अरबों ने स्वीकार किया इराक के विदेशनीति तथा आर्थिक व्यवस्था इंगलैण्ड के नियंत्रण में ही रहा। अतः इराकियों ने ब्रिटिश के इस चाल का विरोध किया और कई जगह विद्रोह हुआ। राजा और अंग्रेजी सरकार के बीच एक संधि हुई कि बिना हाई कमिश्नर के आदेश से राजा कोई आदेश नहीं दे सकता था, किन्तु अरब इस संधि से संतुष्ट नहीं हुआ और उनका विद्रोह चलता रहा

ब्रिटेन और इराक के बीच चार संधियाँ हुई :-

(1) 1922 ई० में इसमें में इराक में ब्रिटेन को कई अधिकार मिले जैसे इराकी सेना को सहायता देना, फैजल राजा को ब्रिटिश सलाहकार नियुक्ति विदेशियों कि रक्षा तथा वैदेशिक मामलों में इराक को सलाह देना, वित्तीय मामलों में इराक को राय देना।

(2) 1926 ई० में दूसरी संधि हुई जिसमें 25 वर्षों कि समय दिया गया कि अगर इराक इस अवधि में स्वतंत्रता पाने योग्य बना लेता है तो उसे स्वतंत्र कर दिया जायेगा। किन्तु ये संधि संसद से पास नहीं हुआ

(3) 1927 ई० में तीसरी सन्धि हुई इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने शर्त रखा कि अगर इराकी योग्य समझे गये तो उसे राष्ट्र संघ के सदस्य बनवाने का प्रयास करेंगे।

(4) अन्त में 1931 ई० में चौथी संधि हुई जिसमें - इराक को ब्रिटेन का युद्ध प्रारम्भ होने पर मदद देने कि शर्तें रखी गई।

(b) इराक में ब्रिटिश राजदूत को विशेष सुविधायें मिले

(c) इराक आवश्यक वस्तुओं कि आयात इंगलैण्ड से करेंगे

APRIL						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Scanned with Can

day

(D) इराक सैनिकों को इंगलैण्ड में ही प्रशिक्षण देगा।
(E) इंगलैण्ड को बगदाद के पश्चिम बसरा के पास अपने हवाई अड्डे बनाने का अधिकार देगा।

इराक ने इस संधि का स्वागत किया। किन्तु अरबी राष्ट्रवादियों ने इसका विरोध किया और ये संधि अपने हितों के विरुद्ध बताया। इराक के निकटवर्ती राज्य ईरान, तुर्की सऊदी अरेबिया से 1925 एवं 1927 ई० में संधि कर मधुर सम्बन्ध कायम करने का प्रयास किया। 3 अक्टूबर 1932 ई० को ईराक राष्ट्र संघ कि सदस्यता पाने में सफल रहा और वे एक स्वाधीन राज्य बन गया।

यह अद्भुत बात है कि ब्रिटेन और इराक इतने अल्प अवधि पर कई संधि किये जिसका कारण अंग्रेजों एवं ईराकियों में दृष्टिकोण में अन्तर था। ब्रिटेन किसी रूप में इराक पर नियंत्रण रखना चाहता था किन्तु इराक इस नियंत्रण से मुक्त होना चाहता था लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बदली कि 1930 ई० में ब्रिटेन को इराक से स्वतंत्रता संबंधी सन्धि करनी पड़ी। अन्ततोगत्वा राष्ट्रसंघ ईराक को राष्ट्र संघ का सदस्य मान लिया। राष्ट्रसंघ से ईराक ने यह वादा किया कि वह ईराक में बसने वाले अल्पसंख्यक जातियों कि रक्षा करेगा, इराक में विदेशियों के किसी भी अधिकारों का हनन नहीं करेगा और मानवीय अधिकारों का आदर करेगा। इसके बाद शासन के समस्त अधिकारी ईराकी स्वयं बन गया। ईराकियों के आत्मबल सफल दृष्टिकोण तथा आपसी एकता के आगे इंगलैण्ड का कुछ भी नहीं चला। ब्रिटेनियों कि उपनिवेशीकरण कि नीति का प्रभाव ईराक पर नहीं पड़ा।